

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1189  
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

सीबीएसई से संबंधित शिक्षकों को उपदान संदाय अधिनियम के अनुसार उपदान

†1189. श्री सु. वैकटेशन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) तमिलनाडु में सीबीएसई से संबंधित ऐसे निजी स्कूलों की संख्या कतनी है, जो 2009 में संशोधित उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार अपने शिक्षकों को, 03.04.1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया, अभी भी उपदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन निजी सीबीएसई स्कूलों द्वारा उपदान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने संशोधित उपदान संदाय अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संवधान की समवर्ती सूची का एक विषय है। केन्द्र सरकार के स्वामत्त्व/व्यवस्थापित स्कूलों के अलावा अन्य स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस लिए, यह मामला संबंधित राज्य सरकार के विनियामक दायरे में आता है और इस प्रकार इन्हें प्राधिकरणों द्वारा इसे लागू किया जाना होता है।

इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) संबंधित उपनियम-2018 में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं:

खंड 5.3 में बताया गया है कि स्कूल उपयुक्त सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों की तर्ज पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों को परिभाषित करेगा, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि-पेंशन योजना (5.3.11) के संबंध में अच्छी तरह से प्रलेखित प्रावधान शामिल हैं।

खंड 5.2.2 में बताया गया है कि "शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान और भत्तों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

बोर्ड के सभी संबंधित स्कूलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आवश्यक संशोधन विधायक बोर्ड के संबंधित उप-नियमों का पालन करें।

\*\*\*\*\*